

प्रेषक

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
माओ उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 25 अगस्त, 2006

विषय : प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (सेंटी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में माओ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया ए अन्य में दिनांक 21 मार्च 2002, दिनांक 06.12.2006 एवं दिनांक 07.2.2006 को पारित आदेश के संदर्भ में उत्तरांचल राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधायें प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 44-एक(1)/XXXVI (1)/2006-6-एक(2)/06 दिनांकित 15 अप्रैल, 2006 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की जिज्ञासा की गई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न स्थिति पर निम्नानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्गत स्पष्टीकरण को तदनुसार पढ़ा जाय :-

पुर्व प्राविधान

स्पष्टीकरण

1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता

(1) प्रत्येक जिला जज, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

(3) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल

1. वाहन सुविधा/वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता

(1) प्रत्येक जिला जज, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जिला जज स्तर के लघुवाद न्यायाधीश, वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला जज तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक स्वतन्त्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल्ड कार की सुविधा के अन्तर्गत 4 न्यायिक अधिकारियों के मध्य 1 पूल कार उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर में 150 लीटर एवं अन्य स्थानों पर 125 लीटर पेट्रोल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

(3) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है, उन्हें निम्नानुसार पेट्रोल/डीजल

देय होगा, जिसके प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी :-

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर । शेष जिले	75 50

नोट:- जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तदनुसार ही किया जायेगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा :

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी	मासिक भत्ता (रुपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	750
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	500

देय होगा, जिसके प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी :-

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमन्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंहनगर । शेष जिले	75 50

नोट:- जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी वाहन है तथा वे उपरोक्तानुसार पेट्रोल/डीजल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पूल कार की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। पूल कारों की आवश्यकता का आगणन तदनुसार ही किया जायेगा।

(4) जिन न्यायिक अधिकारियों के पास अपना निजी स्कूटर/मोटर साइकिल है उन्हें प्रतिमाह 25 लीटर पेट्रोल देय होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक के आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण :

"प्रतिपूर्ति व्यय प्रमाणक" का तात्पर्य पेट्रोल/डीजल के क्रय रसीद से है।

2. अतिथि सत्कार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निम्न दर से अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य होगा :

क्र० सं०	न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी	मासिक भत्ता (रुपये में)
1.	जिला जज/अपर जिला जज	1000
2.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन)	750
3.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन)	500

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रु० 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

4. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

5. दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस. टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी :-

क्र० सं०	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिये निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1.	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2.	अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	1000

3. पोशाक भत्ता

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को 5 वर्ष की अवधि में एक बार रु० 5000 की एक मुश्त राशि पोशाक भत्ता के रूप में देय होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम पांच वर्ष की अवधि 1.11.1999 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

4. समाचार पत्र/पत्रिका

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र व एक पत्रिका (पत्रिका का मूल्य 50 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मूल वाउचर के आधार पर की जायेगी।

5. दूरभाष सुविधा

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के आवास एवं कार्यालय में शासकीय व्यय पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यालय में सभी टेलीफोन एस. टी.डी. युक्त होंगे, परन्तु आवास पर टेलीफोन के साथ एस.टी.डी. की सुविधा केवल उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सीमाओं के अनुसार निःशुल्क काल की सुविधा भी अनुमन्य होगी :-

क्र० सं०	अधिकारी की श्रेणी	2 माह के लिये निःशुल्क काल की सीमा	
		कार्यालय	आवास
1.	जिला जज/सत्र न्यायाधीश	3000	2000
2.	अतिरिक्त जिला जज/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	2000	1000

3.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट	2000	1000
4.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

6. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति

न्यायिक अधिकारियों को बिजली एवं पानी के बिलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 202-एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में देय होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के बीजक की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात् न्यायिक अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगतान के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जायेगी।

7. आवास/मकान किराया भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास शासनादेश संख्या 202-एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों को शासकीय आवास आवंटित होने की स्थिति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात् उनसे शासकीय आवास के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए जाने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

3.	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट	2000	1000
4.	सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मजिस्ट्रेट	1500	750

6. आवास पर विद्युत एवं जल शुल्क की प्रतिपूर्ति

न्यायिक अधिकारियों को बिजली एवं पानी के बिलों की धनराशि का आधा भुगतान न्याय विभाग के शासनादेश संख्या 202-एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में देय होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों के आवासों के बिजली तथा पानी के बीजक की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा अर्थात् न्यायिक अधिकारी को जैसे ही बिजली व पानी का बीजक प्राप्त हो, वह उसका भुगतान करेगा और भुगतान के उपरान्त बीजक और भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर उसकी आधी धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जायेगी।

7. आवास/मकान किराया भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को निःशुल्क आवास शासनादेश संख्या 202-एक(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 8 जून, 2005 के प्रकाश में उपलब्ध होगा जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों को शासकीय आवास आवंटित होने की स्थिति में उन्हें शासकीय आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात् उनसे शासकीय आवास के साथ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क आवास प्रदान किए जाने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

जिन न्यायिक अधिकारीगण को उनके आवेदन के उपरान्त भी सरकारी आवास उनकी प्रास्थिति के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे अपनी प्रास्थिति के अनुरूप आवास किराये पर लेने के लिए अधिकृत होंगे एवं सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा औचित्य प्रमाण पत्र निर्गत करने पर न्यायिक अधिकारी किराये की रसीद उपलब्ध कराकर प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।

जिन न्यायिक अधिकारीगण को उनके आवेदन करने पर उनकी प्रास्थिति (Status), जो शासनादेश संख्या 1257/दो-4-451(2)/91 टी0सी0, दिनांक 08 जून, 1995 से निर्धारित है, के अनुसार सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें निजी आवास में रहने पर भी उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आवास किसया भत्ता देय होगा।"

8. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे न्यायिक अधिकारी का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है तथा न्यायिक अधिकारी इस अवधि में अतिरिक्त पद के न्यायिक कार्य का निष्पादन करते हैं तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

9. अवकाश नकदीकरण

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी सुविधा लेते समय अवकाश लेने के लिये अधिकारी को बाध्य नहीं किया

8. अतिरिक्त प्रभार भत्ता

न्यायिक अधिकारियों को किसी दूसरे पद का प्रभार यदि 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है तथा इस अवधि में उस अधिकारी को अतिरिक्त पद के कार्य का निष्पादन करना पड़ता है, तो उसे अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान के न्यूनतम के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रभार भत्ता अनुमन्य होगा।

9. अवकाश नकदीकरण

न्यायिक अधिकारियों को 2 वर्ष में एक माह तक का अवकाश नकदीकरण लेने की सुविधा अनुमन्य होगी। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की अवधि 1.11.1999 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

जायेगा। इस प्रयोजनार्थ प्रथम 2 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

जिन वर्षों की अवधि हेतु अवकाश नकदीकरण देय होगा, उस अवधि में सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी के खाते में अर्जित अवकाश की गणना अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में की जायेगी, अर्थात् शासनादेश निर्गत होने के पूर्व के उक्त अवधि के अर्जित अवकाश को अवकाश नकदीकरण की गणना के सम्बन्ध में लैप्स हुआ नहीं समझा जायेगा।

"अवकाश नकदीकरण" के "कर मुक्त" भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गई है, परन्तु कर मुक्त करना केन्द्र सरकार का विषय है। अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में केन्द्र सरकार को ऐसे न्यायिक अधिकारीगण के सेवा काल में देय अवकाश नकदीकरण पर कर मुक्त करने हेतु सन्दर्भ प्रेषित किया जा चुका है।

10. अवकाश यात्रा सुविधा

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिये 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने गृह जनपद के लिये अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा के लिये प्रथम 4 वर्ष की अवधि 21 मार्च, 2002 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

10. अवकाश यात्रा सुविधा

न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार अवकाश यात्रा सुविधा भारत में किसी स्थान तक आने-जाने के लिए उपलब्ध रहेगी। अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग करने के लिये 5 वर्ष की निरन्तर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि में अपने गृह जनपद के लिये अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। अवकाश यात्रा सुविधा की अवधि 1.11.1999 से प्रारम्भ मानी जायेगी।

उपरोक्त अवकाश यात्रा सुविधा हेतु रेल/वायुयान की श्रेणी से सम्बन्धित पात्रता की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

अवकाश यात्रा सुविधा लेते समय अर्जित अवकाश लेने के लिए न्यायिक अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि जितनी अवधि अवकाश यात्रा में आवश्यक हो ले सकेंगे एवं उतनी अवधि का ही अर्जित अवकाश कुल अवशेष अर्जित अवकाश से घटाया जायेगा।

11. एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन को सरकारी अस्पतालों/औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों/औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को ₹५०० 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

11. एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान

न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरित होने पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की दशा में एक माह के मूल वेतन के बराबर तथा 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थानान्तरण, जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में एक माह के मूल वेतन के एक तिहाई के बराबर धनराशि एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

12. चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा भत्ता

न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवारजन को सरकारी अस्पतालों/औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों/औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा राज्य के विधान सभा के सदस्य को देय सुविधा, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम 1980 की धारा 18-ए एवं उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के अनुसार समय-समय पर देय है,

अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को ₹५०० 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य होगा।

क्रमशः

2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 21 मार्च, 2002 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिये इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिये यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त आदेश दिनांक 1.11.1999 से प्रभावी माने जायेंगे परन्तु शासनादेश निर्गत होने से पूर्व की किसी अवधि के लिये इन भत्तों/सुविधाओं का उपयोग करने के लिये यथास्थिति, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने इत्यादि जैसी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्व में शासन के आदेशों के अन्तर्गत इन भत्तों/सुविधाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान का समायोजन किया जायेगा।

2- शासनादेश के प्रत्येक प्रस्तर में जहाँ-जहाँ न्यायिक अधिकारी, जिला जज, सत्र न्यायाधीश, अपर जिला जज, अतिरिक्त जिला जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिविल जज(सि०डि०), चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज(जु०डि०) एवं मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ उनके सन्दर्भ में समकक्ष अधिकारी भी पढ़ा जायेगा अर्थात् जो न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा जो प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति के दौरान शासनादेश में उपलब्ध सुविधायें तदनुसार अनुमन्य होंगी।

3- शासनादेश संख्या 44-एक(1)/XXXVI(1)/2006-6-एक(2)/06 दिनांकित 15 अप्रैल, 2006 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

4- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 504/XXVI(5)/2006, दिनांक 25.8.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी।

संख्या : 64-एक(1)(1)/XXXVI(1)/2006-6-एक(2)/06, तददिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्य मंत्री।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के निजी सचिव।
- 4- सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
- 5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
- 7- समस्त जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
- 9- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
- 10- एन.आई.सी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव, न्याय।



चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा भत्ता कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण के साथ-साथ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को भी अनुमन्य होगा।

13. भवन निर्माण/क्रय/भरम्मत/मोटर वाहन क्रय/कम्प्यूटर क्रय के लिए अग्रिम :-

न्यायिक अधिकारीगण को भवन निर्माण/क्रय/भरम्मत के लिए अग्रिम राशि की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या : 537/वि.अनु.-1/2004 दिनांकित 16 जुलाई, 2004 एवं मोपेड/ओटो साईकिल/मोटर-साईकिल/स्कूटर/मोटर कार अग्रिम की धनराशि की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या : 538/वि.अनु.-1/2004 दिनांकित 16 जुलाई, 2004 तथा कम्प्यूटर क्रय के लिए अग्रिम की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या : 538ए/वि.अनु.-1/2004 दिनांकित 16 जुलाई 2004 द्वारा अनुमन्य होगी।

14. विशेष वेतन :-

उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार, न्यायालय समय के पश्चात्, प्रशासनिक कार्य करने वाले, न्यायिक सेवा के सदस्यों को विशेष वेतन देय होगा।

15. पर्वतीय भत्ता :-

न्यायिक अधिकारीगण को पर्वतीय भत्ता समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

16. गृह सहायक भत्ता :-

न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को गृहकार्य के सम्बन्ध में रु० 1250/- मात्र प्रतिमाह गृहकार्य सहायक भत्ता के रूप में देय होगा।

पूर्व में प्राविधान नहीं।

पूर्व में प्राविधान नहीं।

पूर्व में प्राविधान नहीं।

पूर्व में प्राविधान नहीं।